

राज्य वधियकों पर राज्यपाल की शक्ति

प्रलिस के लयः

राज्य वधियकों पर राज्यपाल की शक्ति, [सर्वोच्च न्यायालय](#), [वधिनसभाएँ](#), [अनुच्छेद 200](#), अनुच्छेद 201, राज्यपाल द्वारा वलिंब, [अनुच्छेद 355](#)

मेन्स के लयः

राज्य वधियकों पर राज्यपाल की शक्ति, राज्यपाल द्वारा वलिंब और इससे संबधति मुददे.

चरचा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने कहा की राज्यपाल की सहमतके लयि भेजे गए वधियकों को "जतिनी जल्दी हो सके" वापस कर दयिा जाना चाहयि, उन्हें रोकना नहीं चाहयि, क्योंकि [राज्यपाल की शथिलिता](#) के कारण राज्य [वधिनसभाओं](#) को अनशिचति काल तक इंतजार करना पड़ता है ।

- सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना राज्य द्वारा दायर एक याचकिा में अपने न्यायकि आदेश में कहा की राज्यपाल के पासभेजे गए कई महत्त्वपूर्ण वधियकों को लंबति रखा गया है ।

राज्य वधियकों पर राज्यपाल की शक्तियाँ:

■ अनुच्छेद 200:

- भारतीय संवधिन का अनुच्छेद 200 कसिी राज्य की वधिनसभा द्वारा पारति वधियक को सहमतके लयि राज्यपाल के समकष परसतुत करने की प्रकरथिा को रेखांकति करता है, जो या तो सहमतदे सकता है, सहमतकिो रोक सकता है या राष्ट्रपतिद्वारा वधिार के लयि वधियक को आरकषति कर सकता है ।
- राज्यपाल सदन या सदनों द्वारा पुनर्वधिार का अनुरोध करने वाले संदेश के साथ वधियक को वापस भी कर सकता है ।

■ अनुच्छेद 201:

- इसमें कहा गया है की जब कोई वधियक राष्ट्रपति के वधिार के लयि आरकषति होता है, तो राष्ट्रपति वधियक पर सहमतदे सकता है या उस पर रोक लगा सकता है ।
- राष्ट्रपति वधियक पर पुनर्वधिार करने के लयि राज्यपाल को उसे सदन या राज्य के वधिनमंडल के सदनों को वापस भेजने का नरिदेश भी दे सकता है ।

■ राज्यपाल के पास उपलब्ध वकिलप:

- वह सहमतदे सकता है या वधियक के कुछ प्रावधानों या वधियक पर स्वयं पुनर्वधिार करने का अनुरोध करते हुए इसे वधिनसभा को वापस भेज सकता है ।
- वह राष्ट्रपति के वधिार के लयि वधियक को आरकषति कर सकता है, लेकिन ऐसा केवल तभी कयिा जा सकता है जब राज्यपाल की यह राय है की वधियक उच्च न्यायालय की स्थति को जोखमि में डाल सकता है ।
- वह राष्ट्रपति के वधिार हेतु वधियक को आरकषति कर सकता है । आरकषण अनविरय है जहाँ राज्य वधिनमंडल द्वारा पारति वधियक राज्य उच्च न्यायालय की स्थति को खतरे में डालता है । हालाँकि राज्यपाल वधियक को आरकषति भी कर सकता है यदयिह नमिनलखिति प्रकृति का हो:

- संवधिन के प्रावधानों के खलिाफ
- नीति नदिशक तत्त्वों का वरिध
- देश के व्यापक हति के खलिाफ
- गंभीर राष्टरीय महत्त्व का,
- संवधिन के अनुच्छेद 31A के तहत संपत्तिके अनविरय अधगिरहण से संबधति हो ।

- संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति किसी विधायक को स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है, लेकिन इसे प्रत्येक सदन के दो-तहाई सदस्यों के साथ फरि से पारति कयि जाने के बाद यह विधायक कानून बन जाता है।

नोट:

- अन्य लोकतांत्रिक देशों में सहमत से इनकार की प्रथा देखने को नहीं मिलती है और कुछ मामलों में संविधान द्वारा एक उपाय प्रदान किया जाता है ताकि सहमत से इनकार के बावजूद विधायिका द्वारा पारति विधायक कानून बन सके।

आगे की राह

- संविधान निर्माताओं को इस बात का अनुमान नहीं था कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल किसी विधायक पर कोई कार्रवाई कयि बिना अनश्चितकाल तक के लयि उसे अपने पास रख सकता है।
- राज्यपाल की ओर से टालमटोल एक नई घटना है जिसके लयि संविधान के ढाँचे में कुछ नए बदलाव कयि जाने की आवश्यकता है इसलयि सर्वोच्च न्यायालय को देश में संघवाद के हति में विधानसभा द्वारा पारति विधायक पर नरिणय लेने के लयि राज्यपालों हेतु एक उचित समय सीमा नरिधारति करनी चाहयि।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

?????????:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2018)

1. किसी राज्य के राज्यपाल के वरिद्ध उसकी पदावधिके दौरान किसी भी न्यायालय में कोई दांडकि कार्यवाही संस्थति नहीं की जाएगी।
2. किसी राज्य के राज्यपाल की परलिब्धयिँ और भत्ते उसकी पदावधिके दौरान कम नहीं कयि जाएंगे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई वविकाधीन शक्तयिँ हैं? (2014)

1. भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधरिपति करने के लयि रपिर्ट भेजना।
2. मंत्रयिँ की नयुिक्ता करना।
3. राज्य विधानमंडल द्वारा पारति कतपिय विधायकों को भारत के राष्ट्रपति के वचिर के लयि आरक्षति करना।
4. राज्य सरकार के कार्य संचालन के लयि नयिम बनाना।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा सही है? (2013)

- (a) भारत में एक ही व्यक्त को एक समय में दो या अधिक राज्यों में राज्यपाल नयुिक्त नहीं कयि जा सकता।
- (b) भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नयुिक्त कयि जातें हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश

राष्ट्रपति द्वारा नयिकृत कयि जातैं हैं ।

(c) भारत के संवधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रया अधकथति नहीं है ।

(d) वधायी व्यवस्था वाले संघ राज्यक्षेत्र में मुख्यमंत्री की नयिकृता उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है ।

उत्तर: (c)

प्रश्न. क्या उच्चतम न्यायालय का फैसला (जुलाई 2018) दल्लि के उपराज्यपाल और नरिवाचति सरकार के बीच राजनीतिक कशमकश को नपिटा सकता है? परीक्षण कीजयि । **(मुख्य परीक्षा, 2018)**

प्रश्न. 69वें संवधान संशोधन अधनियम के उन अत्यावश्यक तत्त्वों और वषिमताओं, यदिकोई हों, पर चर्चा कीजयि, जिन्होंने दल्लि के प्रशासन में नरिवाचति प्रतिनिधियों एवं उप-राज्यपाल के बीच हाल में समाचारों में आए मतभेदों को पैदा कर दिया है । क्या आपके वचिर में इससे भारतीय परसिंधीय राजनीति के प्रकार्यण में एक नई प्रवृत्तिका उदय होगा? **(मुख्य परीक्षा, 2016)**

स्रोत: द हद्रि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/governor-s-power-over-state-bills>

